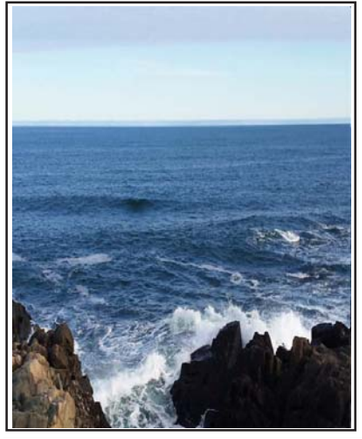

www.adbhutsamachar.com

अद्भुत समाचार

वर्ष – 15 | अंक–41 | RNI-No. : UPHIN/2011/43806 | लखनऊ,शुक्रवार 09 जनवरी, 2026 | प्रातः कालीन संस्करण | (हिन्दी दैनिक) | पृष्ठ–4 | मूल्य 1 रुपया

गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं

त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

गोरखपुर,लखनऊ (08 जनवरी (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार का संकल्प है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय मिले, हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के इलाज में कोई बाधा न आए और भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले भू–माफिया व दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं। वह स्वयं कुर्सियों पर बैठे लोगों तक पहुंचे और उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने सभी प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को यह भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हैं, उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराया जाए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार द्वारा तत्काल धन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में भी मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन–पूजन किया और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाया। इसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण किया और गोशाला पहुंचकर गोसेवा की। मुख्यमंत्री ने गायों और गोवंश को स्नेहपूर्वक गुड़ खिलाया। मंदिर परिसर में परिजनों के साथ आए बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की, उन्हें स्नेह, आशीर्वाद और चॉकलेट देकर प्रसन्न किया।जनता दर्शन और मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश स्पष्ट रहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का समाधान, जरूरतमंदों की सहायता और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के लिए माइक्रोचिपिंग का सुझाव

वकील ने कहा- ये महंगा नहीं पड़ेगा

नयी दिल्ली 08 जनवरी (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस विक्रमनाथ ,जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच सुनवाई कर रही है। कुत्तों पर सुनवाई के दौरान आज भी दिलचस्प दलीलें सामने आईं। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि जब कुत्तों को अचानक हटाया जाता है तो चूहों की आबादी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि वो तो बीमारी फैलाने वाले होते हैं। उन्होंने दावा किया कि कुत्ते संतुलन बनाए रखते हैं।कोर्ट इस मामले में सभी पक्षकारों–डाग लवर्स, कुत्तो काटने के शिकार लोगों , एनिमल राइट एक्टिविस्ट की ओर से पेश वकीलो की दलीलें विस्तार से सुन रहा है।एडवोकेट नकुल दीवान ने सुप्रीम कोर्ट को ट्रैप, न्यूटर और रिलीज मॉडल का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कुत्तों के स्वभाव को देखते हुए यह जरूरी है कि उन्हें उसी जगह वापस छोड़ा जाए, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। दीवान ने यह भी कहा कि बेंगलुरु में कुत्तों की माइक्रो–चिपिंग शुरू हो गई है और यह महंगा नहीं है।सीनियर एडवोकेट नकुल दीवान ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि श्कम्युनिटी कुत्तोंश की बढ़ती तादाद पर रोक लगाने की जरूरत है। दीवान ने कहा कि यह ऐसी समस्या नहीं है, जिसे एक दिन में खत्म किया जा सकता है। हमें कम्युनिटी कुत्तों की बढ़ती संख्या को कम करने की जरूरत है। हम ऐसी स्थिति भी नहीं चाहते, जहां हमारे पास कानून हो, लेकिन उसे लागू न करने की वजह से हमें कोई सख्त कदम उठाना पड़े।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आवारा कुत्तों के मामले में आगे की दलीलें सुनीं, जिसमें वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने तर्क दिया कि यह मुद्दा कुत्तों से आगे बढ़कर सभी आवारा जानवरों तक फैला है और इसके लिए एक संतुलित नजरिए की जरूरत है। एडवोकेट ने

कोर्ट को बताया कि किसी इलाके से कुत्तों को अचानक हटाने से अक्सर अनचाहे नतीजे निकलते हैं, जिसमें चूहों और बंदरों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी शामिल है। उन्होंने कहा कि चूहे, जो कई बीमारियां फैलाते हैं, कुत्तों की मौजूदगी से कंट्रोल में रहते हैं, और चेतावनी दी कि अचानक दखल देने से यह संतुलन बिगड़ सकता है।गुरुवार को सुनवाई फिर से शुरू करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कुत्ते और बिल्लियां स्वाभाविक दुश्मन हैं और बिल्लियां चूहों को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इसका कुत्तों को हटाने से कोई लेना–देना था? हल्के–फुल्के अंदाज में कहें तो, कुत्ते और बिल्लियां दुश्मन हैं। बिल्लियां चूहों को मारती हैं, इसलिए हमें ज्यादा बिल्लियों और कम कुत्तों को बढ़ावा देना चाहिए। यही समाधान होगा।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर पीएम मोदी ने असंख्य सपूतों को किया स्मरण, देशवासियों से की अपील

नयी दिल्ली 08 जनवरी (एजेंसी)प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बृहस्पतिवार से शुरू होने वाला 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''जय सोमनाथ! सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हो रही है। एक हजार वर्ष पूर्व, जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके। बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार–बार पुनरोद्धार होता रहा।'' प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किया। उन्होंने देशवासियों से भी अपील की कि अगर वे भी सोमनाथ गए हैं, तो अपनी तस्वीरें 'हैशटेग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के साथ जरूर साझा करें। मोदी ने कहा, ''सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह अवसर, भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। समय कितना ही कठिन और भयावह क्यों ना रहा हो, उनका संकल्प हमेशा अडिग रहा।'' उन्होंने कहा, ''मैं 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की कुछ झलकियां भी साझा कर रहा हूं। यह वह साल था, जब हमने 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया था। 1951 में यह ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की मौजूदगी में संपन्न हुआ था।''मोदी ने कहा, ''सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और केएम मुंशी के साथ ही कई महान विभूतियों के प्रयास अत्यंत उल्लेखनीय रहे हैं।

पटना सिविल कोर्ट और केरल के जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, ई- मेल के बाद पूरा कोर्ट कराया गया खाली

पटना 08 जनवरी (एजेंसी) ई– मेल के जरिये जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना को बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी में दावा किया गया कि न्यायालय परिसर में आरडीएक्स से बने तीन आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) लगाये गये हैं, जिन्हें आठ जनवरी को विस्फोट किया जायेगा। सूचना मिलते ही न्यायालय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुये जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना के रजिस्ट्रार ने तत्काल आदेश जारी कर सभी अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर खाली करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला बार एसोसिएशन के सचिव से अनुरोध किया गया कि वे सभी अधिवक्ताओं को सूचित कर परिसर को पूरी तरह खाली कराना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रार ने बताया कि यह धमकी भरा ई– मेल सुबह के समय प्राप्त हुआ था। ई– मेल भेजने वाले ने अपना नाम अरुण कुमार बताते हुये खुद को एलटीटीई का सदस्य बताया है। हालांकि, फिलहाल भेजने वाले की पहचान और उसके दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच जिला बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि धमकी की सूचना मिलते ही बार एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुये अविलंब न्यायालय परिसर खाली कराने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि सभी न्यायाधीश, न्यायिक कर्मी और अधिवक्ता सुरक्षित रूप से परिसर से बाहर निकल आये हैं। बम धमकी के बाद न्यायालय परिसर में तैनात सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षित कर लिया। मौके पर बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया, जो कोर्ट परिसर की गहन तलाशी में जुटे हैं। प्रशासन ने बताया है कि सुरक्षा जांच पूरी होने तक न्यायालय परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं, धमकी भरे ई–मेल के स्रोत का पता लगाने और भेजने वाले की पहचान सुनिश्चित करने के लिये साइबर सेल और अन्य जांच एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं।केरल की कासरगोड जिला अदालत में बृहस्पतिवार को बम रखे होने की धमकी मिली, जिसके बाद परिसर को खाली कराकर तलाशी ली गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि धमकी पूर्वाह्न करीब 11 बजे जिला अदालत के आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राप्त हुई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "तुरंत बम निरोधक दस्ते को निरीक्षण के लिए भेजा गया और अदालत परिसर को खाली करा दिया गया। अब तक कुछ भी नहीं मिला है।" उन्होंने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख ने निर्देश दिया है कि अगर धमकी झूठी पाई जाती है तो मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाए। अदालत परिसर खाली कराए जाने के बाद बाहर खड़े एक वकील ने एक टीवी चैनल को बताया कि ईमेल तमिलनाडु से आया था। वकील ने बताया कि पुलिस ने सभी को अदालत परिसर खाली करने के लिए कहा है और तलाशी ली जा रही है।

रेलवे में नौकरी के नाम पर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, बिहार-यूपी समेत 6 राज्य में 15 ठिकानों पर छापामारी

नयी दिल्ली 08 जनवरी (एजेंसी) देश के 6 राज्यों के 15 शहरों में गुरुवार सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी है। ईडी की यह रेड सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे स्कैम को लेकर है। इसके तहत एक संगठित गिरोह लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगता था। उनकी ओर से लोगों को फर्जी ही नियुक्ति पत्र और कॉल लेटर आदि जारी किए जा रहे थे। खासतौर पर भारतीय रेलवे और 40 अन्य सरकारी विभागों में भर्तियों के नाम पर यह स्कैम चल रहा था। रेलवे के अलावा डाक विभाग, वन विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट, लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार, डीडीए और राजस्थान सचिवालय आदि के नाम पर यह ठगी की जा रही थी।यह गैंग फर्जी ईमेल अकाउंट बनाकर लोगों को नियुक्ति पत्र भेजा करता था। ऐसे ईमेल एड्रेस तैयार किए जाते थे, जिन्हें देखने से लगता था कि वास्तव में किसी सरकारी विभाग की ओर से ही भेजा गया है। यही नहीं लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए इस फ्रॉड गैंग ने कुछ लोगों के खातों में 2 से 3 महीने सैलरी भी भेजी थी। इन लोगों को आरपीएफ, टीटीई की नौकरी देने का झांसा दिया जाता था। इन्हें दो से तीन महीने तक सैलरी के नाम पर भी रकम ट्रांसफर की जाती थी। इसी के नाम पर उसने ठगी कर लेते थे। रेलवे में टेक्नीशियन जैसे पदों पर भी यह ठगी की जाती थी।फिलहाल ईडी इस मामले में बिहार, बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में छापेमारी कर रहा है। इन 6 राज्यों के कुल 15 शहरों में ईडी की रेड जारी हैं। यूपी के गोरखपुर में ईडी ने 2 स्थानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा इलाहाबाद में1 और लखनऊ में भी एक जगह छापेमारी चल रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर में एक स्थान पर और मोतिहारी में भी 2 जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी इस गैंग के 2 ठिकानों की जानकारी मिली है। यहां छापेमारी चल रही है। इसके अलावा चेन्नै, राजकोट में भी छापे चल रहे हैं। केरल के भी 4 शहरों में ईडी ने रेड मारी है।

जयराम उमेश का मोदी सरकार पर हमला

बोले- उथल-पुथल भरे दौर में इंडिया-यूएस संबंध

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत-अमेरिका संबंधों को श्अत्यंत उथल-पुथलश भरा बताते हुए कहा कि रूस से व्यापार पर अमेरिकी प्रतिबंध और आउटसोर्सिंग पर टैक्स जैसे विधेयक द्विपक्षीय तनाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि इन नई चुनौतियों ने संबंधों में एक श्नई असामान्य स्थितिश पैदा कर दी है।

नई दिल्ली 08 जनवरी (एजेंसी)कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को भारत–अमेरिका संबंधों में बढ़ते तनाव को उजागर करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को अत्यंत उथल–पुथल भरे दौर से गुजरने वाला बताया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौर की जीत के दौरान व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले लोगों में प्रधानमंत्री भी शामिल थे। ग पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि ट्रंप के दूसरे दौर में व्हाइट हाउस पहुंचने वाले पहले लोगों में प्रधानमंत्री के शामिल होने के बावजूद भारत–अमेरिका संबंध अत्यंत उथल–पुथल भरे दौर से गुजर रहे हैं।जयराम ने आगे विधायी और राजनयिक घटनाक्रमों की ओर भी इशारा किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे भारत की स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। राज्यसभा सांसद रमेश ने अपने पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहयोगी सीनेटर लिंडसे ग्राहम एक विध्ेयक पेश कर रहे हैं, जिसके तहत रूस के साथ भारत के व्यापारिक और अन्य संबंधों के कारण उस पर व्यापक नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे पहले, सीनेटर बर्नी मोरेनो ने एक विधेयक पेश किया था, जिसमें श्आउटसोर्सिंग भुगतानश करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर 25: कर लगाने का प्रस्ताव है।चुनौतियों को बढ़ाते हुए उन्होंने आगे कहा कि भारत की अत्यधिक असुविधा को और बढ़ाने के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप लगातार फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। रमेश ने बदलते हालात पर प्रकाश डालते हुए कहा, "द्विपक्षीय संबंधों में निस्संदेह एक श्नई असामान्य स्थितिश पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री के तुष्टीकरण वाले बयानों के बावजूद, हर दिन एक नई चुनौती है। इससे पहले, 6 जनवरी को, जयराम रमेश ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव को अमेरिकी हस्तक्षेप ने रोक दिया था। उन्होंने बताया कि 10 मई, 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से संपर्क होने के बाद संघर्ष रुका था।

प्रतीक जैन कौन हैं?

ईडी रेड के बाद उनके घर क्यों पहुंची ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने छापेमारी को लेकर भाजपा की जमकर आलोचना की और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक और वित्तीय आंकड़ों को चुराने की कोशिश करने वाले सबसे बड़े डाकू बताया।

नई दिल्ली 08 जनवरी (एजेंसी)इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपीएसी) के सह–संस्थापक और निदेशक प्रतीक जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में आ गए हैं। गुरुवार को आईपीएसी के कोलकाता कार्यालय और जैन के आवास पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा छापेमारी के दौरान काफी हंगामा हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यालय पहुंचीं और कुछ फाइलें अपने कब्जे में लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और एजेंसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। ममता बनर्जी ने छापेमारी को लेकर भाजपा की जमकर आलोचना की और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक और वित्तीय आंकड़ों को चुराने की कोशिश करने वाले सबसे बड़े डाकू बताया।प्रतीक जैन कौन हैंप्रतीक जैन एक इंजीनियर हैं जो बाद में राजनीतिक सलाहकार बन गए। उन्होंने 2015 में विनेश चंदेल और ऋषि राज सिंह के साथ मिलकर आईपीएसी की सह–स्थापना की। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीआईटी) बॉम्बे से धातुकर्म अभियांत्रिकी और सामग्री विज्ञान की पढ़ाई की, जहां उन्होंने एक्सिस म्यूचुअल फंड में इंटर्नशिप भी की। बाद में वे सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के संस्थापक सदस्य बने, जिसे लिंक्डइन पेज पर भारत में जवाबदेह शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक गैर–लाभकारी संगठन के रूप में वर्णित किया गया है।

टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद केंद्र का बड़ा कदम, राज्यों से प्रभावित शिक्षकों का विस्तृत ब्योरा तलब

नई दिल्ली ।टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) से जुड़े माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 और 17 नवंबर 2025 के निर्णायक फैसलों के बाद केंद्र सरकार ने देश–भर में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल की है। शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित शिक्षकों की संख्या, उनकी सेवा–स्थिति तथा संभावित प्रभावों का विस्तृत विवरण शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है।संयुक्त सचिव (संस्थागत एवं प्रशिक्षण) द्वारा 3 दिसंबर 2025 को जारी डी.ओ. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पाँच वर्ष से कम का समय शेष है, उन्हें टीईटी उत्तीर्ण किए बिना सेवा में बने रहने की अनुमति होगी, हालांकि पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य रहेगा। वहीं, आरटीई अधिनियम से पूर्व नियुक्त तथा जिनकी सेवानिवृत्ति में पाँच वर्ष से अधिक समय शेष है, ऐसे शिक्षकों के लिए दो वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने तथा केवल टर्मिनल लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान लागू हो सकता है।

केंद्र सरकार के अनुसार, इन निर्णयों के बाद व्यक्तिगत शिक्षकों, विभिन्न शिक्षक संगठनों और सांसदों की ओर से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों में यह गंभीर चिंता व्यक्त की गई है कि सेवा के अंतिम चरण में खड़े शिक्षकों के लिए टीईटी जैसी परीक्षा उत्तीर्ण करना न केवल अत्यंत कठिन है, बल्कि मानसिक दबाव और असुरक्षा भी उत्पन्न करता है। इसके साथ ही दशकों के अनुभव से युक्त शिक्षकों के संभावित बाहर होने से राज्यों की शिक्षा व्यवस्था में शैक्षणिक रिक्तता पैदा होने की आशंका भी जताई गई है।इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित शिक्षकों की सटीक संख्या का आकलन करें, उपलब्ध कराए जाने वाले आँकड़ों का पूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करें, राज्य–विशेष प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करें तथा प्रभावित शिक्षकों को संभावित राहत देने से जुड़े कानूनी एवं नीतिगत विकल्पों पर स्पष्ट टिप्पणियाँ भेजें।

शिक्षा मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया है कि राज्यों के भर्ती नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (छब्ज्म्) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इस संदर्भ में केंद्रीय विद्यालय संगठन (झटै) के अद्यतन भर्ती नियमों का उल्लेख करते हुए राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे भी समयबद्ध रूप से अपने भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करें।केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह समस्त जानकारी और टिप्पणियाँ 16 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

शिक्षा जगत में इस पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहला अवसर है जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केवल औपचारिक अनुपालन तक सीमित न रहकर, उसके व्यावहारिक प्रभावों और संभावित राहत उपायों पर संगठित एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें लाखों अनुभवी शिक्षकों के हित में कोई संतुलित, व्यवहारिक और न्यायसंगत समाधान निकाल पाती हैं।

यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स गायब!वोटर्स लिस्ट पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, लगाया गंभीर आरोप

लखनऊ 08 जनवरी (एजेंसी)समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने गुरुवार को भाजपा पर उत्तर प्रदेश में फर्जी वोट बनाने की कोशिश का आरोप लगाया। यह आरोप विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से 28 लाख नाम हटाए जाने के बाद लगाया गया है। उन्होंने जनता से अपने नाम की जांच करने का आग्रह किया ताकि उनके वोट प्रभावित न हों। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि जब वे मतदान केंद्र पर पहुंचें तो मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। यादव ने कहा कि जनता को अपने वोट को लेकर आश्वस्त रहना चाहिए और भाजपा के झूठे प्रचार में नहीं फंसना चाहिए.. पहली बार हम देख रहे हैं कि भाजपा नेता उत्तर प्रदेश में एसआईआर से परेशान हैं। भाजपा नेता कह रहे हैं कि मतदाताओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा फर्जी वोट डालती है तो समाजवादी पार्टी के लोग, जो श्पीडीए प्रहरीश का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। पूरी भाजपा फर्जी वोट डालने के मिशन पर है, क्योंकि इतने सारे वोट काटे गए हैं.. मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों को वोटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे रहे हैं।मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जनगणना चरण के पूरा होने के बाद मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की घोषणा की। मसौदा मतदाता सूची से कुल 289 करोड़ नाम हटा दिए गए। प्रेस को संबोधित करते हुए नवदीप रिनवा ने कहा, ह्हमें लगभग 12 करोड़ 55 लाख जनगणना प्रपत्र प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि इतने लोगों ने प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके यह दर्शाया कि उनके नाम मसौदा सूची में शामिल किए जाने चाहिए। ऐसे मतदाताओं की संख्या 4623 लाख थी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 217 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं अपना निवास स्थान बदल चुके हैं अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराते समय जिस घर में रह रहे थे उसे छोड़ चुके हैं स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं ।

सम्पादकीय

एक बेतुका आदेश

हाल के दिनों में देश की शीर्ष अदालत से लेकर आम विमर्श तक में आवारा कुत्तों का मामला सुर्खियों में रहा है। इस संवेदनशील, जटिल व विवादास्पद मुद्दे से जुड़े कई तरह के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में बिहार के एक नगर निगम के बेतुके फरमान को लेकर आलोचना की जा रही है। यह निर्णय न केवल बेतुका है बल्कि हास्यास्पद भी है। बिहार के सासाराम के नगर निगम ने शिक्षकों से सड़कों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की गिनती करने को कहा है। दरअसल, अदालत के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों की इस बाबत जवाबदेही तय की गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों व गिरते परीक्षा परिणाम के बावजूद शिक्षकों को गैर–शिक्षण कार्यों में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर हर छोटे–बड़े सरकारी अभियान में शिक्षकों की जिम्मेदारी लगाना प्रशासनिक विफलता को भी उजागर करता है। कभी जनगणना, कभी चुनावी ड्यूटी तो कभी आपदा सर्वेक्षण, और अब कुत्तों की गिनती का बेतुका काम शिक्षकों के जिम्मे लगा दिया गया है। दरअसल, बिहार के शिक्षक विषम परिस्थितियों के चलते पहले ही अत्यधिक दबाव में हैं। जिसके कारण वे शैक्षणिक जिम्मेदारियों व गैर–शिक्षण दायित्वों के लगातार बढ़ते बोझ के बीच संतुलन बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि हर इस तरह का व्यवधान कक्षा के समय, पाठ योजना और छात्रों की सहभागिता को गहरे तक प्रभावित करता है। निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा बच्चे के विकास की नींव रखती है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक रहता है। वर्षों से पेश की जा रही एएसईआर रिपोर्टों में कई बार उजागर किया गया है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम देश में सबसे कमजोर रहा है। जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में जब पहले ही बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहता है तो शिक्षकों को एक और गैर–शैक्षणिक कार्य के लिये कक्षाओं से बाहर निकालना, निस्संदेह शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम ही कहा जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि यह आदेश कई वास्तविक खतरों से भरा है। आवारा कुत्तों की गिनती करना शिक्षण के कागजी कार्य के समान सहज नहीं है। निश्चित रूप से अनेक शिक्षक ऐसे होंगे जो कुत्तों से डरते भी होंगे। खासकर शिक्षिकाओं के लिये यह कार्य खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ लोग इस गणना प्रक्रिया में वास्तविक खतरे का सामना भी कर सकते हैं। इस बात का संकेत शीर्ष अदालत की टिप्पणी में भी मिलता है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि किसी कुत्ते के मन को पढ़ना या यह अनुमान लगाना असंभव है कि कोई जानवर कब आक्रामक हो जाएगा। निश्चित रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों को ऐसे कार्य करने के लिए कहना, उनकी सुरक्षा के लिये भी चुनौती होगी। खासकर तब जब आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं और रेबीज से होने वाली जीवन क्षति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में नगर निगम के आदेश की तार्किकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण और जन सुरक्षा उपायों को लागू करने में नगरपालिकाओं की विफलता पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद एक स्थानीय निकाय ने अपनी मूल जिम्मेदारी शिक्षकों पर थोपकर इसका जवाब दिया है। निश्चित रूप से यह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा है। निर्विवाद रूप से इस बेतुके आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की जरूरत है। सही मायनों में नगरपालिका के अधिकारियों को अपना काम करना चाहिए और शिक्षकों को भी अपना काम करने की आजादी दी जानी चाहिए। यह समस्या केवल शिक्षकों की ही नहीं है बल्कि यह हमारे नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। ऐसे में शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्यत्र काम सौंपना, कहीं न कहीं छात्रों और छात्राओं को शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित करने जैसा भी है।

समुद्र अब केवल व्यापार का रास्ता नहीं रहा

वह महाशक्तियों की ताकत परखने की प्रयोगशाला बन गया है

इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया रूस के कदम ने। रूस ने इस टैंकर की सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए। यह साफ संदेश था कि मास्को इस जहाज को केवल एक व्यापारिक पोत नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला मान रहा है।

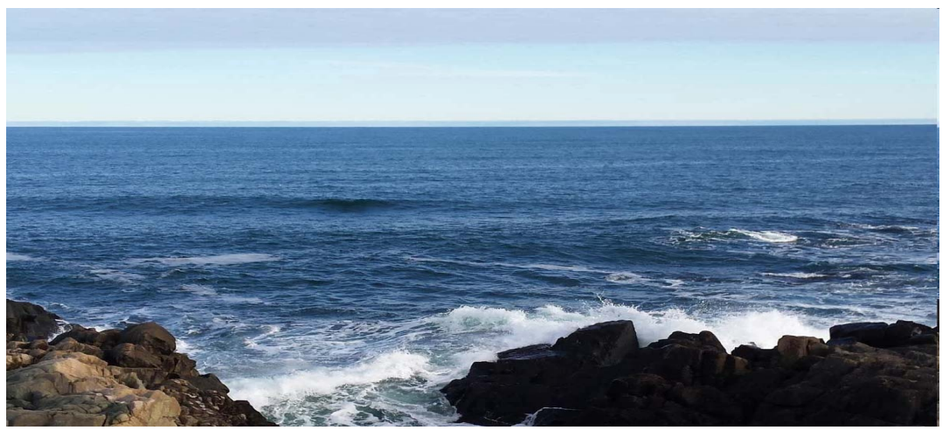

कुछ सप्ताह से अमेरिका और रूस के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा था। जानकारी के अनुसार, अमेरिका का आरोप था कि यह जहाज प्रतिबंधों को तोड़कर वेनेजुएला का कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में लगा हुआ था। अमेरिका का कहना है कि यह तेल अवैध तरीके से बेचा जा रहा था और इससे वेनेजुएला सरकार को आर्थिक सांस मिल रही थी। इसी आधार पर अमेरिका ने समुद्र में इस टैंकर को रोकने और अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया।इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया रूस के कदम ने। रूस ने इस टैंकर की सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए। यह साफ संदेश था कि मॉस्को इस जहाज को केवल एक व्यापारिक पोत नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला मान रहा है। समुद्र में अमेरिकी और रूसी नौसेनाएं आमने सामने रहीं। आखिरकार अमेरिका ने टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी।रूस ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि अमेरिका खुले तौर पर समुद्री डकैती पर उतर आया है। वहीं अमेरिका ने इसे प्रतिबंध लागू करने की वैध कार्रवाई बताया। इस एक टैंकर ने दो महाशक्तियों को ऐसी टकराव की स्थिति में ला दिया, जिसने शीत युद्ध की यादें ताजा कर दीं।देखा जाये तो यह घटना किसी एक जहाज की कहानी नहीं है। यह उस बदलती हुई दुनिया की तस्वीर है, जहां ताकतवर देश नियम बनाते भी हैं और उन्हें तोड़ते भी हैं। समुद्र के बीच एक तेल टैंकर आज अमेरिका और रूस के बीच शक्ति संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। अमेरिका का रवैया साफ है। वह वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। तेल वेनेजुएला की जीवन रेखा है और अमेरिका उसी रेखा को काट देना चाहता है। टैंकर की जब्ती यह बताती है कि अब अमेरिका केवल आर्थिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उन्हें बंदूक और युद्धपोत के दम पर लागू करने की नीति अपना चुका है।वहीं, रूस के लिए यह केवल वेनेजुएला का सवाल नहीं है। यह उसकी वैश्विक साख और प्रभाव का सवाल है। अगर रूस अपने सहयोगी देशों के व्यापार और संसाधनों की रक्षा नहीं कर पाता, तो उसकी ताकत केवल भाषणों तक सिमटकर रह जाएगी। इसी कारण मॉस्को ने पनडुब्बी और युद्धपोत भेजकर यह दिखा दिया कि वह समुद्र में भी अमेरिका को खुली चुनौती देने से नहीं डरेगा।सामरिक दृष्टि से देखा जाये तो यह टकराव बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बात, यह संघर्ष समुद्री मार्गों को युद्ध क्षेत्र में बदल रहा है। अब समुद्र केवल व्यापार का रास्ता नहीं रहा, बल्कि वह महाशक्तियों की ताकत परखने की प्रयोगशाला बन गया है। दूसरी बात, पनडुब्बियों और युद्धपोतों की तैनाती बताती है कि किसी भी समय एक छोटी घटना बड़े सैन्य टकराव में बदल सकती है।देखा जाये तो तेल की राजनीति इस पूरे खेल के केंद्र में है। वेनेजुएला के पास विशाल तेल भंडार हैं और उस पर नियंत्रण का मतलब है वैश्विक ऊर्जा बाजार पर प्रभाव। अगर अमेरिका इसमें सफल होता है, तो वह तेल की कीमतों और आपूर्ति को अपने हितों के अनुसार मोड़ सकेगा। वहीं रूस और उसके साथी देश चाहते हैं कि पश्चिमी दबदबा टूटे और वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी हो।साथ ही दो महाशक्तियों की इस भिडंत का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहला असर ऊर्जा कीमतों पर होगा। अनिश्चितता बढ़ते ही तेल और गैस की कीमतें उछलेंगी, जिसका बोझ सीधे आम जनता पर पड़ेगा। दूसरा असर वैश्विक राजनीति पर होगा। छोटे और मध्यम देश दबाव में आ जाएंगे कि वे किस खेमे में खड़े हों।साथ ही यह टकराव दुनिया को नए गुटों में बांट सकता है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी समूह होगा, तो दूसरी तरफ रूस के साथ खड़े वे देश होंगे जो अमेरिकी वर्चस्व से असहज हैं। यह विभाजन व्यापार, तकनीक और सुरक्षा सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अंतरराष्ट्रीय कानून अब ताकतवर देशों के लिए केवल एक हथियार बनता जा रहा है। जब जरूरत हो तो कानून की दुहाई दी जाती है और जब जरूरत न हो तो उसे ताक पर रख दिया जाता है। इससे वैश्विक व्यवस्था की नींव कमजोर होती है।बहरहाल, यह कहना गलत नहीं होगा कि यह टैंकर भविष्य की झलक है। आने वाले समय में ऐसे टकराव और तेज होंगे। समुद्र, आकाश और ऊर्जा संसाधन नई जंग के मैदान बनेंगे। अमेरिका और रूस की यह रस्साकशी केवल दो देशों की नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ी हुई है।

अमर्त्य सेन को नोटिस, अब यही बचा था

पिछले साल अगस्त में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया को संवेदनशीलता से नहीं संभाला गया तो बड़ी संख्या में गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। श्री सेन ने उस नौकरशाही प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया था जो नागरिकों से सख्त दस्तावेजी साक्ष्य मांगती है, जबकि शायद उनके पास वे दस्तावेज उपलब्ध न हों। उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं और समय–समय पर संशोधन आवश्यक हैं लेकिन ये मौलिक अधिकारों की कीमत पर नहीं होने चाहिए। अमर्त्य सेन ने कहा था कि कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं हैं। कई लोग वोट नहीं दे सकते.. अगर हालात को थोड़ा सुधारने के नाम पर कई लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो यह एक गंभीर गलती बन जाती है, सिर्फ एक गलती को सुधारने के लिए सात नयी गलतियां करना जायज नहीं ठहराया जा सकता।एसआईआर पर ऐसी नकारात्मक टिप्पणी पहली बार नहीं हुई थी, देश का विपक्ष लगातार इन्हीं सवालों को उठाते आया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो बाकायदा वोटर अधिकार यात्रा ही इस मुद्दे पर निकाल दी और साथ ही चुनाव आयोग के सामने वोट चोरी के सबूत भी पेश किए। जिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करने कहा। अमर्त्य सेन से ऐसी कोई मांग नहीं की गई, लेकिन उन्हें प.बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नोटिस भेजकर आयोग के सामने पेश होने कहा गया।जी हां, नरेन्द्र मोदी के राज में अब ये भी मुमकिन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को नाम की वर्तनी गलत होने के नाम पर चुनाव आयोग नोटिस भेज सकता है। जब एक नोबेल विजेता और विश्व विख्यात नागरिक के साथ भारत सरकार का सलूक ऐसा है, तो फिर आम आदमी के लिए वह कितनी हेय दृष्टि रहती है, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। प.बंगाल में एसआईआर को लेकर कई किस्म के विवाद सामने आ रहे हैं। सत्तारुढ़ टीएमसी ने दावा किया है कि बूढ़े और बीमार लोगों तक को चुनाव आयोग नोटिस भेजकर परेशान कर रहा है। आरोप है कि कम से कम 70 लोगों की मौत इस प्रक्रिया की वजह से हो चुकी है। ये बेहद गंभीर बात है और सुप्रीम कोर्ट इन मौतों पर स्वतरू संज्ञान लेकर नए सिरे से चुनाव आयोग से पूछताछ करेगा ऐसी उम्मीद है। बहरहाल, आम लोगों को परेशान करने और अकाल मौतों के आरोपों के बीच एक नया विवाद अमर्त्य सेन को नोटिस जारी करने पर खड़ा हो गया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस पर सवाल उठाए तो चुनाव आयोग ने इसे टाइपो की गलती बताया और नोटिस जारी करने वाले बीएलओ को सस्पेंड कर दिया। हालांकि कायदे से इसमें ज्ञानेश कुमार को दो पंक्ति का ही सही लेकिन खेद प्रकट करना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस ने सही कहा कि अमर्त्य सेन को नोटिस जारी करना बंगाल और भारत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले एक महान व्यक्तित्व का अपमान है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमर्त्य सेन को दिया गया नोटिस दर्शाता है कि कैसे बंगाल में प्रभावशाली आवाजों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले अभिनेता देव और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजे गए थे। मानो उपलब्धि, ईमानदारी और गरिमा का अब कोई महत्व ही नहीं रह गया हो। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भारत की बौद्धिक संपदा और मूल्यों को विश्व मंच पर पहुंचाया। आज, उनके कद का एक सार्वजनिक व्यक्ति भी भाजपा नियंत्रित चुनाव आयोग के हाथोंअपमानित हो रहा है।ध्यान रहे कि नोबेल पुरस्कार विजेता की दिवंगत माता अमिता सेन, 2002 में बंगाल में हुए एसआईआर (जनगणना) के दौरान मतदाता सूची में थीं। अमर्त्य सेन ने 2014 में बंगाल में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया था और उसी वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। जब राज्य में एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर को शुरू हुई, तो सेन के नाम से एक एसआईआर जनगणना प्रपत्र जारी किया गया। उनके चचेरे भाई संताभानु सेन ने भरा हुआ प्रपत्र बीएलओ (राज्य परिवहन अधिकारी) को जमा कर दिया। एसआईआर में अमर्त्य सेन के नाम की वर्तनी में अंतर पाया गया था। इसी पर नोटिस भेजा गया। हालांकि अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि सेन को गलती सुधारने के लिए बीरभूम जिले के बोलपुर स्थित निर्धारित कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने कहा कि एक बीएलओ (चुनाव अधिकारी) हार्वर्ड के अर्थशास्त्री सेन के पैतृक निवास शांति निकेतन स्थित प्रतीची जाकर आवश्यक कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर को मतदाता सूची में नाम की वर्तनी जैसी छोटी गलतियों को सुधारने का अधिकार है। इसलिए अमर्त्य सेन के मामले में भी सुधार प्रशासनिक स्तर पर ही किया जाएगा। बता दें कि आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की विसंगति से जुड़े नोटिस तुरंत डाउनलोड कर चार से पांच दिनों के भीतर संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाए जाएं। इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस निर्देश के हिसाब से तो बीएलओ ने सही कार्रवाई की, लेकिन उसे सस्पेंड किया गया, जबकि यहां असल जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार की है। और केवल बंगाल ही नहीं, इससे पहले बिहार में जो विसंगतियां पाई गईं, और अब उत्तरप्रदेश की मसौदा सूची में जो गड़बड़ी सामने आ रही है, सब पर ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए।उप्र में छह जनवरी को जो वोटर लिस्ट सत्यापन की सूची आई है, उसमें 2.89 करोड़ (18 प्रतिशत) नाम कट गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट में 46.23 लाख मृत, 2.17 करोड़ लोग स्थानांतरित और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर थे, अब 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं। इस सूची पर विपक्ष फिर सवाल उठा रहा है कि आखिर पौने तीन करोड़ मतदाता अगर योग्य थे ही नहीं तो अब तक चुनाव आयोग को इसका पता क्यों नहीं चला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गहरी आपत्ति जताते हुए कहा है कि 18 प्रतिशत नाम कटने का मतलब है कि प्रदेश में हर पांचवां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। वहीं उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराता है बीडीसी के जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रधानों के चुनाव जो कराता है उसने बीते महीने दिसंबर में ही एक सूची तैयार की जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 12 करोड़ 70 लाख वोट है। लेकिन जनवरी की एसआईआर लिस्ट बताती है कि कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। तो सवाल ये है कि करीब–करीब 4 करोड़ शहरी मतदाता कहां चले गए? कैसे उनके नाम जोड़े जाएंगे? यह वाकई गंभीर सवाल है, जिस पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल और उनके पूरे परिवार का नाम भी एसआईआर में बाहर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना घर बदला था। क्या घर बदलना और घुसपैठिया होना एक ही है, जिस वजह से मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।उप्र में छह जनवरी को जो वोटर लिस्ट सत्यापन की सूची आई है, उसमें 2.89 करोड़ (18 प्रतिशत) नाम कट गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट में 46.23 लाख मृत, 2.17 करोड़ लोग स्थानांतरित और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर थे, अब 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं। इस सूची पर विपक्ष फिर सवाल उठा रहा है कि आखिर पौने तीन करोड़ मतदाता अगर योग्य थे ही नहीं तो अब तक चुनाव आयोग को इसका पता क्यों नहीं चला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गहरी आपत्ति जताते हुए कहा है कि 18 प्रतिशत नाम कटने का मतलब है कि प्रदेश में हर पांचवां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। वहीं उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराता है बीडीसी के जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रधानों के चुनाव जो कराता है उसने बीते महीने दिसंबर में ही एक सूची तैयार की जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 12 करोड़ 70 लाख वोट है। लेकिन जनवरी की एसआईआर लिस्ट बताती है कि कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। तो सवाल ये है कि करीब–करीब 4 करोड़ शहरी मतदाता कहां चले गए? कैसे उनके नाम जोड़े जाएंगे? यह वाकई गंभीर सवाल है, जिस पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल और उनके पूरे परिवार का नाम भी एसआईआर में बाहर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना घर बदला था। क्या घर बदलना और घुसपैठिया होना एक ही है, जिस वजह से मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा ह

पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के विरुद्ध थे

तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध करते हुए 17 से अधिक पत्र लिखे थे। राष्ट्रपति तथा कैबिनेट मंत्रियों को लिखे पत्रों में उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जरूरत पर प्रश्न उठाया था और उन्हें इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने से बहुत हतोत्साहित किया था। उन्होंने सरकारी संचार माध्यमों को निर्देश दिया कि समारोह की कवरेज कम से कम की जाए।

उन्होंने भारतीय दूतावासों को भी निर्देश दिए कि वह सोमनाथ ट्रस्ट को सहायता प्रदान न करें। कुल मिलाकर इन पत्रों ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के विरोध तथा सहजता को प्रदर्शित किया। 21 अप्रैल 1951 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें आश्वस्त किया कि सोमनाथ के द्वारों को लेकर गढ़े जा रहे अख्यान 'पूरी तरह से गलत' हैं और इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 28 अप्रैल 1951 को भारत के तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री आर.आर. दिवाकर को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय को सोमनाथ मंदिर के निर्माण संबंधी कवरेज बारे प्रचार को निष्क्रम करने को कहा और कहा कि यह समारोह विश्व में भारत की छवि को क्षति पहुंचा रहा है। उन्होंने 2 मई 1951 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 2 पत्र लिखे जिनमें उन्होंने अथाह जन समर्थन तथा अपने खुद के सहयोगियों की शमूलियत का सम्मान न करते हुए उनसे कहा कि भारत सरकार सोमनाथ मंदिर से संबंधित समारोहों से खुद को दूर रख रही है। 1 अगस्त 1951 को मुख्यमंत्रियों को लिखे अपने पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर किए जा रहे जोरदार प्रचार को भारत की धर्मनिरपेक्ष की छवि को कमजोर करने वाला बताया और कहा कि इससे विदेशों में बहुत बुरा प्रभाव जा रहा है। पाकिस्तान के विद्वेषपूर्ण प्रोपेगंडा पर प्रश्न उठाने की बजाय उन्होंने तर्क दिया कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने 20 जुलाई 1950 को तत्कालीन केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री के.एम. मुंशी को लिखे पत्र में प्रश्न उठाया कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए, जबकि देश में आवासों की कमी है तथा आध्यक स्थिति खराब है। 13 जून 1951 को उप–राष्ट्रपति डा. एस. राधाकृष्णन को लिखे अपने पत्र में उन्होंने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह को एक अनावश्यक 'कोलाहल' बताया और स्वीकार किया कि उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को इसमें शामिल होने से रोकने का प्रयास किया था। 17 अप्रैल 1951 को चीन में भारत के राजदूत के.एम. पाणिक्कर को लिखे अपने पत्र में नेहरू ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर में राष्ट्रपति के दौरे के प्रभावों को कम करने का प्रयास किया था। तत्कालीन सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री यू.एन. ढेबार को 21 अप्रैल 1951 को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर समारोह के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सरकारी फंड पर आपत्ति जताई तथा तर्क दिया कि मंदिर एक सरकारी मामला नहीं है। 22 अप्रैल 1951 को नवानगर के जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने सोमनाथ ट्रस्टियों के पवित्र नदियों के जल तथा मिट्टी के लिए विदेशी मिशनों तक पहुंचने पर चिंता व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि इससे एक गलत सरकारी धारणा बनती है। उन्होंने इसे एक निजी मामला बताते हुए भारत सरकार को इससे दूर रखा। यहां तक कि सौराष्ट्र सरकार की भी इससे जुडने और सरकारी फंडों को खर्च करने को लेकर आलोचना की। दो दिन बाद ही जाम साहिब को ही 24 अप्रैल 1951 को लिखे पत्र में उन्होंने खुले तौर पर सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह को 'नव जागरणवाद' बताते हुए इसकी खुल कर आलोचना की और चेतावनी दी कि राष्ट्रपति तथा मंत्रियों का इसमें शामिल होना राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरे प्रभाव डालेगा। 17 अप्रैल 1951 को विदेशी मामलों के मंत्रालय में महासचिव तथा विदेश सचिव को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने निर्देश दिया कि दूतावासों को सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से पवित्र नदियों के पानी को लेकर किए गए आवेदन पर जरा भी ध्यान न दिया जाए, जो स्पष्ट दर्शाता है कि हिंदू धार्मिक गतिविधियों से वह कितने असहज थे। 9 मई 1951 को विदेश मंत्रालय के सचिव एस. दत्त को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने इस समारोह के साथ भारत सरकार की किसी भी तरह की संबंधता को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर की। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त खूब चंद को 19 मार्च 1951 को लिखे अपने पत्र में पं. नेहरू ने सोमनाथ के अभिषेक के लिए सिंधु नदी के जल के इस्तेमाल को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया और विदेश सचिव के माध्यम से यह संदेश भिजवाया कि इस याचना को उनकी स्वीकृति नहीं है। 2 मार्च 1951 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को लिखे पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने पूर्ण खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्हें सोमनाथ के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति का शामिल होना बिल्कुल पसंद नहीं। केंद्रीय गृहमंत्री सी. राजगोपालाचारी को 11 मार्च 1951

पर्वों का संगमः जीवन में सहज-सजग शुरुआत का आनंद

संगीता मित्तल

नववर्ष जब लोहड़ी और मकर संक्रांति के साथ दस्तक देता है, तो समय मानो एक क्षण ठहरकर हमें कुछ याद दिलाने आता है। आंगनों में जलती लोहड़ी की अग्नि, अन्न की सांझेदारी, सूर्य का उत्तरायण होना–ये केवल पर्व नहीं, जीवन के संतुलन के संकेत हैं। यह संयोग हमें बताता है कि जीवन में सच्ची शुरुआत कभी हड़बड़ी से नहीं होती, वह हमेशा लय और सजगता से जन्म लेती है। नया साल हमसे तेज दौडने की मांग नहीं करता। वह हमसे सजग होकर मंजिल तक पहुंचने को प्रेरित करता है। लेकिन हर जनवरी के साथ हमारे मन में एक अजीब–सी बेचैनी घर कर जाती है–और बेहतर, और तेज, और अधिक साबित करने की होड़ में हड़बड़ी। लक्ष्य ऊंचे करने, टाइम–टेबल ठूंसने और साल के शुरुआती दिनों में ही उपलब्धियां दिखाने का दबाव। जैसे समय स्वयं हमसे हिसाब मांग रहा हो। जबकि सच्ची शुरुआत कभी दबाव में नहीं होती। वह तब होती है, जब हड़बड़ी की जगह सजगता हो, जब गति से पहले संतुलन बनाया जाए। आज की अधिकांश महत्वाकांक्षाएं प्रेरणा से नहीं, तुलना से जन्म लेती हैं। हम उधार की समय–सीमाओं और परिभाषाओं में सफलता को नापने लगे हैं। ऐसी परिभाषाएं, जो हमारे जीवन के भीतर की ऋतु, लय और सीमा को शायद ही मानती हों। नतीजा यह है कि जनवरी के अंत में ही बहुत से लोग थक चुके होते हैं। यह थकान अनुशासन की कमी नहीं, सुनने व समझने की कमी का परिणाम है। यह असफलता नहीं, असंतुलन है। कर्म समस्या नहीं है। बिना भीतर टिके किया गया कर्म ही कई बार संकट का रूप ले लेता है। सजगता रहित महत्वाकांक्षा शोर बन जाती है। वह आगे तो धकेलती है, पर यह नहीं पूछती कि दिशा सही है या नहीं। सजगता महत्वाकांक्षा को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसे शुद्ध करती है। पर्वों में छिपा जीवन–विज्ञान रू भारत के फसल पर्व इसी समय आते हैं–यह संयोग नहीं, संकेत है। ये पर्व हमें बिना उपदेश दिए सिखाते हैं कि जीवन केवल महत्वाकांक्षा से नहीं, संतुलन से चलता है। अग्नि शुद्ध करती है। भोजन पोषण देता है और संतुलन उपचार करता है। जब हम अग्नि को कृतज्ञता से, भोजन को संयम से और शरीर को लय से सम्मान देते हैं, तो मन स्वतरू स्थिर होने लगता है। ये पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की गहरी समझ हैं। लोहड़ी हमें सिखाती है कि जो पक चुका है, जो भारी हो गया है, उसे छोड़ देना चाहिए। मकर संक्रांति का संदेश है कि रोशनी की ओर मुडना अचानक नहीं, धीरे.धीरे होता है। दोनों मिलकर एक शाश्वत सत्य कहते हैं–विकास कठोर होना जरूरी नहीं। परिवर्तन जल्दबाजी में नहीं होता और सजग प्रगति अंततरू शांति बन जाती है। सजगता को अक्सर जीवन से पलायन समझ लिया जाता है। जबकि सच यह है कि सजगता जीवन से सबसे गहरा संवाद है। अपनी सांस, थकान और इच्छा को बिना जजमेंट देख पाना–यह आत्मिक ईमानदारी है और वही साहस है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि जब कर्म विवशता से नहीं, सजगता से उपजता है, तो मन स्थिर होता है, प्रतिक्रियाएं नरम पड़ती हैं और स्पष्टता जन्म लेती है। सहज शुरुआत धीमी इसलिए नहीं होती कि उसमें ऊर्जा कम है, बल्कि इसलिए कि उसमें दिशा का सम्मान होता है। जब हम नया साल सजगता से शुरू करते हैं, तो सवाल बदल जाते हैं। 'मैं कितना हासिल कर सकता हूं' की जगह 'क्या आवश्यक है' सामने आता है। सहजता कमजोरी नहीं है। वह बिना हिंसा की शक्ति है। आज की थकान शारीरिक से अधिक मानसिक है। कठोर आत्मसंवाद, अवास्तविक अपेक्षाएं और निरंतर स्वयं पर निगरानी–इनमें कोई भी जीवित तंत्र फलता–फूलता नहीं। श्रीमद् भगवत गीता यहां भी करुणा से मार्ग दिखाती है–'उद्धरेदात्मनाऽत्मानं' अर्थात स्वयं को स्वयं उठाओ, गिराओ मत। जैसे बीज केवल कोमल मिट्टी में फूटता है, वैसे ही भीतर का परिवर्तन सुरक्षा और करुणा में होता है। सफलता की नई परिभाषा रू 'बर्नआऊट', चिंता और भावनात्मक दूरी व्यक्तिगत असफलता नहीं, सामूहिक संकेत हैं। ये बताते हैं कि हमारी सफलता की मौजूदा परिभाषा मानव स्वभाव से मेल नहीं खा रही। उपस्थिति के बिना उत्पादकता खोखली है। भीतर के आधार के बिना उपलब्धि टिकती नहीं। सजगता को चुनना लक्ष्य छोडना नहीं है। यह लक्ष्य को भय की जगह स्पष्टता से आगे बढने देना है। नववर्ष और लोहड़ी–मकर संक्रांति (उत्तरायण) के इस संगम पर शायद सबसे बड़ा संकल्प यह हो सकता है कि हम समय को जीतने नहीं, समझने की कोशिश करें। बोलने से पहले देखें। तय करने से पहले सुनें। आगे बढ़ें, पर भीतर आक्रामकता के बिना। सहज शुरुआत अनिर्णय नहीं, चलती हुई बुद्धि है। इस राह पर हम पीछे नहीं छूटते। हम पहुंचते हैं, जड़ में टिके, उपस्थित और शांत आत्मविश्वास के साथ। सहजता हमसे ताकतवर बनने को नहीं कहती, वह हमें सच्चा बनने को कहती है। नव वर्ष, लोहड़ी–मकर संक्रांति (उत्तरी भारत), पोंगल (दक्षिणी भारत), उत्तरायण (गुजरात, राजस्थान), माघ बिहू (असम), मकर विलक्कू (केरल) का संगम हमें सहजता व सजगता से जीवन को आगे बढ़ाने का संदेश देता है।

आयुष्मान योजना में क्लेम निस्तारण में बड़ा सुधार
एक साल में पेंडेंसी 10.75 लाख से घटकर 3 लाख, 4,649 करोड़ का भुगतान

लखनऊ,(संवाददाता) । योगी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जहां लाभार्थी परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर पूरी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते एक वर्ष में आयुष्मान योजना के अंतर्गत क्लेम निस्तारण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों से प्राप्त होने वाले क्लेम के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में क्लेम की पेंडेंसी जहां 10 लाख 75 हजार तक पहुंच गई थी, वहीं दिसंबर 2025 तक इसे घटाकर मात्र 3 लाख कर दिया गया है, जिसे भी शीघ्र ही निस्तारित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर माह औसतन 2 लाख से अधिक क्लेम प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले क्लेम का समयबद्ध निस्तारण एक बड़ी चुनौती है, इसके बावजूद यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुराने लंबित मामलों के साथ–साथ नए क्लेम का भी नियमित और व्यवस्थित ढंग से निस्तारण हो, ताकि अस्पताल बिना किसी हीलाहवाली के आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज जारी रखें।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर क्लेम निस्तारण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मेडिकल ऑडिट व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। साचीज की एसीईओ पूजा यादव ने बताया कि मेडिकल ऑडिटरों की संख्या 40 से बढ़ाकर 130 कर दी गई है, जिससे क्लेम की जांच प्रक्रिया में तेजी आई है। इसके साथ ही क्लेम प्रोसेसिंग डेस्क की संख्या भी 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत क्लेम का भुगतान 30 दिनों की निर्धारित समय–सीमा, यानी टर्न अराउंड टाइम के भीतर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एजेंसी स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और लंबित मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है।साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों को क्लेम के सापेक्ष कुल 4,649 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार न केवल गरीबों के इलाज की गारंटी दे रही है, बल्कि अस्पतालों के आर्थिक हितों की भी पूरी तरह से रक्षा कर रही है, ताकि वे बिना किसी दबाव के जरूरतमंद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें।योगी सरकार की इन नीतियों से क्लेम पेंडेंसी में आई कमी, समयबद्ध भुगतान व्यवस्था और मजबूत मेडिकल ऑडिट प्रणाली ने अस्पतालों का भरोसा बढ़ाया है। इसका सीधा लाभ गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मिल रहा है, जिन्हें अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कर्ज लेने या अपनी संपत्ति बेचने की मजबूरी से बड़ी राहत मिली है।

बीबीएयू में 10 से 12 जनवरी तक तीन दिवसीय विश्वविद्यालय दिवस समारोह, शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय पर रहेगा विशेष फोकस

लखनऊ(संवाददाता) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की स्मृति में 10 से 12 जनवरी 2026 तक तीन दिवसीय विश्वविद्यालय दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन शैक्षणिक उत्कृष्टता, सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह समारोह बौद्धिक विमर्श, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सामुदायिक सहभागिता के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करेगा, साथ ही शिक्षण, शोध, नवाचार और विस्तार गतिविधियों में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को रेखांकित करेगा।विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने विश्वविद्यालय दिवस समारोह को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों का उत्सव बताते हुए कहा कि यह दिवस शिक्षण, शोध, नवाचार और खेलकूद के क्षेत्र में अर्जित सफलताओं की सार्थकता को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ये उपलब्धियां शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं। कुलपति ने सभी को इन उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध उत्पादकता और सामाजिक प्रभाव को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी दोहराया कि बीबीएयू बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के मूल्यों और विरासत से प्रेरणा लेकर समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अपने विजन की दिशा में निरंतर अग्रसर है।तीन दिवसीय विश्वविद्यालय दिवस समारोह का औपचारिक उद्घाटन 10 जनवरी को किया जाएगा। पूरे आयोजन के दौरान शैक्षणिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों की एक समृद्ध श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसमें प्रतिष्ठित व्याख्यान, पैनल चर्चाएं, छात्र–केंद्रित गतिविधियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रदर्शनी और संवादात्मक कार्यक्रम शामिल होंगे। समारोह में विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य, छात्र, अधिकारी, कर्मचारी, पूर्व छात्र तथा शिक्षा जगत और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विशिष्ट अतिथि सहभागिता करेंगे। विशेष सत्रों में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों और मूल्यों पर केंद्रित चर्चाएं होंगी, जिनका उद्देश्य विश्वविद्यालय समुदाय को समानता, समावेशन और उत्कृष्टता के आदर्शों को आत्मसात करने की प्रेरणा देना है।समारोह का समापन 12 जनवरी 2026 को आयोजित समापन सत्र के साथ होगा, जिसमें छात्रों, संकाय सदस्यों और विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह समारोह न केवल उपलब्धियों का उत्सव होगा, बल्कि भविष्य की शैक्षणिक दिशा और सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता को भी मजबूती प्रदान करेगा।उल्लेखनीय है कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ ने ऑल इंडिया एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय ने समग्र श्रेणी में 69वां स्थान, विश्वविद्यालय श्रेणी में 37वां स्थान, विधि में 12वां स्थान, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 21वां स्थान, फार्मेसी में 23वां स्थान और प्रबंधन श्रेणी में 79वां स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय को 3.72 स्कोर के साथ नैक की प्रतिष्ठित 'ए' ग्रेड मान्यता भी प्राप्त है, जो इसके सुदृढ़ शैक्षणिक परिवेश, गुणवत्ता संवर्धन और निरंतर प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं की सुविधा को नई ऊँचाई
चार पर्यटन सूचना केंद्रों से 20 लाख से अधिक लोग लाभान्वित

लखनऊ(संवाददाता) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन और मार्गदर्शन में संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ 3 जनवरी से भव्य और दिव्य स्वरूप में हो चुका है। आस्था, सुविधा और सुव्यवस्था के संगम के रूप में विकसित हो रहा यह मेला अब केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से भी देश–दुनिया में नई पहचान बना रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योगी सरकार द्वारा व्यापक, प्रभावी और आधुनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रयागराज के प्रमुख स्थलों पर चार अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। 3 जनवरी से अब तक इन सूचना केंद्रों के माध्यम से करीब 20 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक लाभान्वित हो चुके हैं। इस वर्ष माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आगमन का अनुमान है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सही, सरल और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्रों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रयागराज के प्रमुख पर्यटन स्थलों से संबंधित विस्तृत जानकारी वाली पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही गाइड बुक, प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड की सूची और शहर भ्रमण से जुड़ी आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और संतुष्टि को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। इसी सोच के तहत पर्यटन सूचना केंद्रों पर पंजीकृत पेइंग गेस्ट हाउस, धर्मशाला और अन्य ठहरने के विकल्पों की जानकारी भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है।इन सूचना केंद्रों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से माघ मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों, स्वच्छता अभियानों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधारित वीडियो भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। साथ ही विस्तृत सेक्टर मैप लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु आसानी से यह जान सकें कि किस सेक्टर में कौन–कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और वहां तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है। ये चार अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्र परेड ग्राउंड, नागवासुकी मंदिर, प्रयागराज छिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन और अरैल घाट के समीप स्थापित किए गए हैं। यहां प्रयागराज के साथ–साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की पर्यटन पुस्तिकाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि पर्यटक प्रदेश की समृद्ध पर्यटन विरासत से भी परिचित हो सकें।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप माघ मेला 2026 को स्वच्छ, सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक–अनुकूल बनाया गया है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा सूचना, गाइड और आवास से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि हर आगंतुक को सहज, सुरक्षित और यादगार अनुभव प्राप्त हो सके।प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृति अभिजात ने कहा कि माघ मेला केवल आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार की प्राथमिकता है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम अनुभव मिले, जिसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।गौरतलब है कि वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित दिव्य, भव्य और स्वच्छ कुंभ को पूरी दुनिया ने सराहा था और यूनेस्को द्वारा इसे 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' के रूप में मान्यता दी गई थी। उसी ऐतिहासिक सफलता की कड़ी में माघ मेला 2026 भी योगी सरकार की कुशल व्यवस्थाओं, श्रद्धा और सुव्यवस्था का जीवंत उदाहरण बनता हुआ नजर आ रहा है।

बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाले तीन शातिर चोर गिरफ्तार, नकदी, मोबाइल और वाहन बरामद

लखनऊ(संवाददाता)। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के उत्तरी जोन अंतर्गत थाना अलीगंज पुलिस ने बंद घरों और दुकानों की रेकी कर चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 7,420 रुपये की नकदी, दो मोबाइल फोन, एक ड्राइविंग लाइसेंस तथा घटना में प्रयुक्त टाटा मोटर्स इंट्रा ट30 वाहन बरामद किया है, जिसे सीज कर दिया गया है।पुलिस के अनुसार 7 जनवरी 2026 को मोहिबुल्लापुर थाना मड़ियांव निवासी आयुष यादव ने थाना अलीगंज में तहरीर दी थी कि वह एक दूध डेयरी में काम करता है, जहां से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 12 हजार रुपये नकद और उसका ड्राइविंग लाइसेंस चोरी कर लिया गया। इस तहरीर के आधार पर थाना अलीगंज में मुकदमा संख्या 07ध्2026 धारा 305 और 331(4) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।मामले के खुलासे के लिए थाना अलीगंज पुलिस टीम ने साक्ष्य संकलन और मुखबिर की सूचना के आधार पर 8 जनवरी 2026 को ईदगाह के पास कूड़ा डालने वाले मोड़ के पास से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में शमद, सलीम और अरशद अली शामिल हैं, जो सभी थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के निवासी हैं और जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष बताई गई है।पुलिस तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 7,420 रुपये नकद, एक रेडमी 14ब 5ळ मोबाइल, एक ओप्पो रेनो 2 मोबाइल तथा आयुष यादव के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त वाहन न्द्32ंछ5265 टाटा मोटर्स इंट्रा ट30 (डाला) भी बरामद किया गया। वाहन के कागजात न दिखा पाने पर पुलिस ने उसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया। बरामदगी के आधार पर दर्ज मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी भी की गई है।पूछताछ के दौरान तीनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले रविंद्र गार्डन क्षेत्र में एक दुकान का शटर तोड़कर चोरी की थी, इसके बाद मड़ियांव इलाके में भी एक दुकान का शटर तोड़कर नकदी चोरी की। अभियुक्तों ने बताया कि चोरी की गई रकम का अधिकांश हिस्सा खर्च हो चुका है और जो शेष बची थी, वही पुलिस द्वारा बरामद की गई है।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शमद और सलीम पर पूर्व में अलीगंज, तालकटोरा और ठाकुरगंज थानों में चोरी और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज रहे हैं। वहीं अरशद अली के खिलाफ हजरतगंज, अलीगंज, गोमतीनगर और ठाकुरगंज थानों में चोरी, आबकारी अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं।इस पूरी कार्रवाई को थाना अलीगंज के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों के खिलाफ अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और उनके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

मतदाता सूचियों में भारी अंतर पर अखिलेश यादव का सवाल, तीन करोड़ मतदाता गायब होने का आरोप

लखनऊ(संवाददाता) समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की विभिन्न मतदाता सूचियों में सामने आ रहे बड़े अंतर को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार है या डबल ब्लंडर की सरकार, यह जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा, पंचायत और नगर निकाय चुनावों की मतदाता सूचियों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मतदाताओं का अंतर दिखाई दे रहा है, जिसका अब तक कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।अखिलेश यादव के अनुसार निर्वाचन आयोग और अन्य आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी बताती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा मतदाता सूची (एसआईआर के बाद, प्रारूपदृ2026) में 12.56 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायत मतदाता सूची (एसआईआर संशोधित अस्थायीदृ2026) में यह संख्या 12.70 करोड़ बताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश नगर निकाय मतदाता सूची (चुनाव वर्षदृ2023) में लगभग 4.32 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि नगर निकाय मतदाता सूची में कुछ त्रुटियाँ हैं और एसआईआर के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत यानी करीब 1.08 करोड़ मतदाताओं की कटौती होती है, तब भी संशोधन के बाद नगर निकाय मतदाता सूची में लगभग 3.24 करोड़ मतदाता शेष रहने चाहिए।उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति में उत्तर प्रदेश पंचायत मतदाता सूची और नगर निकाय मतदाता सूची का कुल योग लगभग 15.80 करोड़ होना चाहिए, जबकि विधानसभा मतदाता सूची में केवल 12.56 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। ऐसे में लगभग 3 करोड़ मतदाता आखिर कहाँ गायब हो गए, यह एक गंभीर और चिंताजनक प्रश्न है।समाजवादी पार्टी ने इन आंकड़ों के आधार पर आशंका जताई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में निर्वाचन आयोग पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के मताधिकार को सीमित या दबाने का प्रयास कर रहा है। पार्टी ने मांग की है कि इस पूरे मामले पर निर्वाचन आयोग और सरकार पारदर्शी तरीके से स्थिति स्पष्ट करें, ताकि लोकतंत्र में जनता का विश्वास बना रहे।

ग्रामीणों के लिए बड़ी सुविधा: ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू हुई आधार सेवा केंद्र योजना

लखनऊ,(संवाददाता) । उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब ग्रामवासियों को नया आधार बनवाने, अपडेट कराने या प्रमाणीकरण के लिए ब्लॉक या शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार ने प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आधार सेवा केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन केंद्रों में सभी आवश्यक उपकरण लगाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण सीधे अपने गांव में ही आधार से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकें।पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिवालय में स्थापित इन केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायक करेंगे। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी भी सीधे गांव के स्तर पर आएगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यूआईडीएआई (न्प्क।प्) ने पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्रार आईडी और इंपैनलमेंट एजेंसी (ईए) आईडी जारी कर दी है, जिससे संचालन अधिकृत और पारदर्शी तरीके से होगा।आधार सेवा केंद्रों की स्थापना से ग्रामीणों को आधार नामांकन, अपडेट और प्रमाणीकरण में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से सीधे जुड़े रहेंगे। योजना के पायलट चरण में सफलता मिलने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

अमित कुमार सिंह ने कहा कि यह पहल डिजिटल सशक्तिकरण को मजबूत करेगी और ग्राम स्तर पर विकास की सोच को साकार करेगी। ग्राम सचिवालय में ही नया आधार बनवाने और अपडेट करवाने की सुविधा मिलने से ग्रामीणों का समय और श्रम बचेगा और उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे उनके पास मिलेगा। यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार की "आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत" की दिशा में एक ठोस प्रयास है, जो ग्रामीणों को डिजिटली सशक्त बनाने के साथ–साथ उनके जीवन को आसान और सुरक्षित बनाएगा।

लखनऊ नगर निगम ने अहमदाबाद के कचरे से विद्युत उत्पादन परियोजना का किया स्थलीय अध्ययन

लखनऊध्अहमदाबाद, (संवाददाता) । नगर निगम लखनऊ ने नॉलेज एक्सचेंज एवं कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद में नगर ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन परियोजना का अध्ययन और स्थलीय निरीक्षण किया। इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों को समझना और उन्हें लखनऊ में लागू करने की संभावनाओं का आकलन करना था।इस अवसर पर नगर निगम लखनऊ का प्रतिनिधिमंडल माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में अहमदाबाद पहुंचा। निरीक्षण दल में उपाध्यक्ष श्रीमती चरनजीत गांधी, पार्षद दल के उपनेता सुशील तिवारी 'पम्मी', कई माननीय पार्षदगण, अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित संयंत्र का विस्तृत अवलोकन किया, जिसमें प्रतिदिन लगभग 1000 मीट्रिक टन नगर ठोस अपशिष्ट से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि इस संयंत्र में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से तैयार आरडीएफ (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) का उपयोग किया जाता है। मार्टिन रिवर्स ग्रेट फायरिंग तकनीक के माध्यम से बॉयलर में अपशिष्ट का सुरक्षित दहन किया जाता है, जिससे प्रति घंटे लगभग 65 टन भाप उत्पन्न होती है। इस भाप से 15 मेगावाट क्षमता की टरबाइन चलाई जाती है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है।यह परियोजना पब्लिकदृप्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित की गई है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 375 करोड़ रुपये है और यह संयंत्र करीब 14 एकड़ भूमि में स्थापित है। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना न केवल कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरण–अनुकूल निस्तारण में सहायक है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।नगर निगम लखनऊ ने इस अवसर का उपयोग लखनऊ में "वेस्ट टू वेल्थ" आधारित सस्टेनेबल मॉडल विकसित करने के लिए किया। प्रतिनिधिमंडल ने तकनीक, लागत, संचालन और पर्यावरणीय लाभों का गहन अध्ययन किया। साथ ही, कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत कार्बन क्रेडिट क्लेम से जुड़ी संभावनाओं पर भी विचार किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने पर नगर निगम को प्रतिवर्ष लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।नगर निगम के अधिकारियों ने इस पहल को न केवल पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया, बल्कि इसे लखनऊ में आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाली एक मॉडल परियोजना के रूप में देखा।

"रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो" के नारे के साथ 16 से 22 जनवरी तक यूपी में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा, मिर्जापुर से सारनाथ तक चलेगी 100 किमी की लड़ाई: संजय सिंह

लखनऊ(संवाददाता)। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा हालात पर तीखा हमला बोलते हुए घोषणा की है कि बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव, पेपर लीक, महंगाई, वोट चोरी और लोकतंत्र पर हो रहे लगातार हमलों के खिलाफ आम आदमी पार्टी 16 जनवरी से 22 जनवरी तक "रोजगार दोदृसामाजिक न्याय दो" पदयात्रा निकालेगी। यह पदयात्रा पार्टी की तीसरे चरण की यात्रा होगी, जो मिर्जापुर के शहीद उद्यान से शुरू होकर वाराणसी के सारनाथ तक जाएगी। करीब 100 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता से सीधे संवाद कर उनके मुद्दों को सड़क पर उठाएगी।संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को जानबूझकर हिंदूदृमुसलमान, दलितदृसवर्ण, अगड़ादृपिछड़ा में बांटकर नफरत की राजनीति में झोंक दिया गया है, ताकि जनता अपनी असली समस्याओं पर सवाल न पूछ सके। उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, बुनकर, रेहड़ीदृपटरी वाले और नौजवान जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समाज को आपस में लड़ाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि "क्या फर्क पड़ता है" जैसी सोच को छोड़ें और इस पदयात्रा से जुड़कर अपने हक की आवाज बुलंद करें।संजय सिंह ने कहा कि आज हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि करोड़ों युवाओं के पास काम नहीं है। किसान खाद की एक बोरी और अपनी फसल के सही दाम के लिए लाइन में खड़ा होकर मर रहा है। नौजवान जब नौकरी मांगने जाता है तो उसे लाठियां मिलती हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में मोमबत्ती की रोशनी में ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया गया है, बेरोजगारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है, फिर भी जनता को व्हाट्सएप के जरिये यह समझाया जा रहा है कि भारत महान बन रहा है और सवाल पूछना गुनाह है।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति ने सबसे ज्यादा गरीबों को कुचला है। बुनकर बेरोजगार हो गए हैं, रेहड़ीदृपटरी वालों की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन किसी को यह सोचने की फुर्सत नहीं कि उनके परिवार कैसे जिएंगे। जो भी सरकार से सवाल पूछता है, उसे फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है और फर्जी एनकाउंटर तक की घटनाएं सामने आ रही हैं। संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को डराने और धमकाने की राजनीति चल रही है और समाज को इस कदर सुन्न कर दिया गया है कि उसे इन सब बातों से फर्क ही नहीं पड़ता।उन्होंने कहा कि असली सवाल यह नहीं है कि समाज में दिक्कतें हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि इन दिक्कतों के खिलाफ हमें दिक्कत क्यों नहीं हो रही। उन्होंने आजादी के आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने यह सोच लिया होता कि "क्या फर्क पड़ता है", तो देश कभी आजाद नहीं होता। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, आपातकाल के समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोगों ने जेलें भरीं और लाठियां खाईं, क्योंकि वे सिर झुकाकर नहीं जीना चाहते थे और लोकतंत्र व अधिकारों को बचाना चाहते थे।संजय सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में नौजवान सबसे ज्यादा पीड़ित है। चपरासी से लेकर लेखपाल, सिपाही, दरोगा और पीसीएस तक की परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती में घोटाले सामने आ रहे हैं। पिछड़े वर्ग और दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है। सामाजिक भेदभाव की हालत यह है कि मंदिर की सीढ़ियों पर बुजुर्गों का अपमान किया जा रहा है, कथावाचकों की छुट्टियां कटवा दी जाती हैं और दलित होने के कारण सीआरपीएफ के जवान को घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ बेरोजगारी की नहीं, बल्कि सम्मान और सामाजिक न्याय की भी है।उन्होंने बताया कि इसी लड़ाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने यह पदयात्रा शुरू करने का फैसला किया है।

आदिवासियों की आवाज दबाने के लिए झूठे मुकदमे और गिरफ्तारी, लोकतंत्र पर सीधा हमला: श्याम लाल पाल

लखनऊ(संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भाकपा माले लिबरेशन के उत्तर प्रदेश राज्य सचिव कामरेड सुधाकर यादव और मिर्जापुर की जिला सचिव कामरेड जीरा भारती की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और वन विभाग चार पीढ़ियों से बसे गरीब आदिवासी परिवारों को जबरन बेदखल करने की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। विरोध करने पर नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराएं लगाना पूरी तरह अन्यायपूर्ण और तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है।श्याम लाल पाल ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस गाड़ी में बूट से मारपीट और जेल के भीतर भी उत्पीड़न की खबरें अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय हैं। गांव के गरीबों के घरों और खेतों पर बुलडोजर चलाना तथा आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को निशाना बनाना सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों और आदिवासियों को डराने के लिए प्रशासनिक ताकत का खुला इस्तेमाल किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि मिर्जापुर जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के तेंदुआ खुर्द गांव में वन विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से आदिवासी परिवारों को बेदखल करने के लिए रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनें लगाई गईं। लहलहाती फसलों को रौंद दिया गया और महिलाओं व लड़कियों के साथ अभद्रता की गई। हैरानी की बात यह है कि जिस समय यह पूरी कार्रवाई हो रही थी, उस समय कामरेड सुधाकर यादव और जीरा भारती मौके पर मौजूद भी नहीं थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगा दी गईं।श्याम लाल पाल ने कहा कि इस मामले में पांच गांव वालों सहित कुल सात लोग जेल में बंद हैं और यह पूरी कार्रवाई भाजपा सरकार की विपक्ष के प्रति प्रतिशोध की राजनीति को उजागर करती है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि जो सरकार गरीबों, आदिवासियों और उनके हक की आवाज उठाने वालों को इस तरह कुचलना चाहती है, वह संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहेगी और आदिवासियों व उत्पीड़ितों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन

मानव सम्पदा पोर्टल के सर्वर अनुरक्षण के कारण 09 से 12 जनवरी तक सेवाएं रहेंगी बाधित

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग के मानव सम्पदा पोर्टल से संबंधित सर्वर के अनुरक्षण (ˆ म त अ म त डंपदजमदंदबम) का कार्य दिनांक 09 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक कुल चार दिवस की अवधि में किया जाएगा। इस दौरान मानव सम्पदा पोर्टल से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहेंगी।इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती मोनिका रानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि वे उक्त अवधि को ध्यान में रखते हुए मानव सम्पदा पोर्टल से जुड़े अपने आवश्यक कार्यों की योजना पूर्व में ही सुनिश्चित कर लें।

गोरखपुर में जनता दर्शनः सीएम योगी ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं, कहा,हर पीड़ित को मिलेगा न्याय और इलाज

गोरखपुर।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान करना सरकार का संकल्प है और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूरी तत्परता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो तथा भूमि कब्जाने वाले भू–माफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं। वे स्वयं कुर्सियों पर बैठे लोगों तक पहुंचे और उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने सभी प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए त्वरित, निष्पक्ष और संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए तथा लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर आए लोगों से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंद मरीजों के उच्च स्तरीय उपचार का आकलन (इस्टीमेट) शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराया जाए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तत्काल धनराशि उपलब्ध कराएगी। राजस्व एवं कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में भी शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन–पूजन किया और अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाया। इसके पश्चात मंदिर परिसर का भ्रमण किया और गोशाला पहुंचकर गोसेवा की। उन्होंने गायों और गोवंश को स्नेहपूर्वक गुड़ खिलाया।

मंदिर परिसर के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने परिजनों के साथ आए बच्चों से मुलाकात कर उन्हें स्नेह, आशीर्वाद और चॉकलेट दी।

70वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित हुआ बैंकिंग एवं वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम

(हरिशंकर मिश्र)

लखीमपुर खीरी। 70वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, लखीमपुर खीरी के राजन कुमार श्रीवास्तव कमान्डेंट के नेतृत्व में एवं प्रदीप सिंह यसहायक कमान्डेंट कि उपस्थिति में ई समवाय, कतर्नियाघाट में जवानों को वित्तीय सशक्तिकरण एवं बैंकिंग जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैंकिंग एवं वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य जवानोंध्कार्मिकों को ब।च्ध्ध्च्तंउपसपजंतल ।बबवनदज से जुड़ी बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रेरित करना रहा । कार्यक्रम के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ;ैठप्द्ध गिरजापुरी के शाखा प्रबंधक द्वारा उपस्थित कार्मिकों को ब।च्ध्ध्च्तंउपसपजंतल ।बबवनदज से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें वेतन खाता, विशेष बैंकिंग सुविधाएँ, बीमा लाभ, ऋण सुविधाएँ, डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ, खाता नामांकन प्रक्रिया तथा भविष्य में मिलने वाले आर्थिक लाभों के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया । इस अवसर पर डिजिटल बैंकिंग के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन लेन–देन में सावधानियाँ, बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव एवं आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाने के तरीकों पर भी प्रकाश डाला गया । बैंक प्रबंधक द्वारा उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि सही जानकारी एवं सतर्कता से आर्थिक जोखिमों से बचा जा सकता है । कार्यक्रम के दौरान कार्मिकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक समाधान किया गया । उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि जवानों का वित्तीय रूप से सशक्त होना न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह उनकी सेवा दक्षता एवं मनोबल को भी सुदृढ़ करता है । कार्यक्रम के अंत में कार्मिकों से अपील की गई कि वे उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं का सही एवं सुरक्षित उपयोग करें तथा अपने सहकर्मियों एवं परिवारजनों को भी वित्तीय जागरूकता के प्रति प्रेरित करें। उपस्थित कार्मिकों ने इस कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताया ।

70वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।

मौत का कुआं ब्रेक डांस वह झूले धूम मचा रहे मेले में

धौरहरा खीरी।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुदरिया में वार्षिक मेले का विधिवत शुभारंभ बीती 5 जनवरी को हुआ था जिसकी लिखित अनुमति वर्तमान सक्षम अधिकारियों ने मेला कमेटी को दी लेकिन इसी बीच बिना अनुमति के मेला परिसर में मौत का कुआं, ब्रेक डांस,बडी नाव व ऊंची हाइट का झूला भी मेले में धूम मचा रहें हैं। जिसकी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति मेला कमेटी के पास नहीं है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुदरिया में वार्षिक मेले का आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी माह में 15 दिनों के लिए होता रहा है। मेले का अयोजन कराने के लिए रजिस्टर्ड कमेटी भी मौजूद हैं मेले में ग्रामीण परिवेश से जुड़े संसाधनो के साथ गर्म कपड़े व खाने पीने के स्टाल परिसर में प्रतिवर्ष लगते हैं।जिसकी लिखित अनुमति पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार प्रतिवर्ष देते है।मेला कमेटी द्वारा 1 जनवरी 26 को नीव पूजन किया गया मेले का विधिवत शुभारंभ 5 जनवरी से शुरू कराया गया।

अटल आवासीय विद्यालयों में अनिवार्य होगा दैनिक समाचार पत्र पठन, भाषाई व तार्किक कौशल पर विशेष जोर

लखनऊ।अध्यक्ष, बी0ओ0सी0डब्ल्यू कल्याण बोर्ड एवं प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग डॉ. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम ने विद्यालयों में नियमित समाचार पत्र पठन (न्यूजपेपर रीडिंग) की संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा के साथ–साथ सामान्य ज्ञान, भाषाई पकड़ और आलोचनात्मक सोच को सशक्त बनाना आवश्यक है। इसके लिए विद्यार्थियों को समाचार पत्रों के नियमित पठन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।उन्होंने अवगत कराया कि इस संबंध में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 23 दिसंबर 2025 को विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इन्हीं निर्देशों के क्रम में समस्त अटल आवासीय विद्यालयों में संबंधित गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से दैनिकचर्या में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए हैं।डॉ. शन्मुगा सुन्दरम ने बताया कि प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय में प्रतिष्ठित एवं उच्च गुणवत्ता वाले हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार पत्र नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाएं। विद्यार्थियों को समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान के साथ–साथ विज्ञान, अर्थव्यवस्था, नवीन विकास और खेल से संबंधित विषयों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाए।उन्होंने निर्देशित किया कि प्रार्थना सभा के उपरांत, कक्षा में पठन–पाठन प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिदिन 10 मिनट समाचार पठन के लिए निर्धारित किए जाएं। साथ ही प्रतिदिन पाँच नए अथवा कठिन शब्द उनके अर्थ सहित बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएं। विद्यालय के मुख्य डिस्प्ले बोर्ड पर 'आज का सुविचार' अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए।कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में एक बार संपादकीय लेखों पर आधारित मौलिक लेखन या समूह चर्चा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, कनिष्ठ वर्ग के छात्रों के लिए विज्ञान, पर्यावरण और खेल जैसे विषयों पर आधारित न्यूज क्लिपिंग स्क्रैपबुक तैयार कराई जाए।मानसिक विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से समाचार पत्रों में प्रकाशित सुडोकू, शब्द पहेली और ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी पर समय–समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को समाचार पत्रों की संरचना और प्रस्तुतीकरण से प्रेरणा लेते हुए अपने विद्यालय की एक त्रैमासिक समाचार पत्र या पत्रिका तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसका संपादन विद्यार्थियों की टीम द्वारा किया जाएगा। इसमें विद्यालय की गतिविधियों और उपलब्धियों को समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को छोटे समूहों में वैज्ञानिक तथ्यों और प्रक्रियाओं पर चर्चा के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

डॉ. शन्मुगा सुन्दरम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के साथ–साथ उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

INDUS FOOD–2026 में उत्तर प्रदेश पवेलियन का भव्य उद्घाटन, कृषि निर्यात को मिलेगी नई रफ्तारः दिनेश प्रताप सिंह

लखनऊ।प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने आज नोएडा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी प्छक्न्ै थ्व्व्क्.2026 के हॉल नंबर.8 में निदेशालय कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पवेलियन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के निर्यात–योग्य कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों के प्रदर्शन का अवलोकन करते हुए निर्यातकों का उत्साहवर्धन किया।

उद्घाटन के पश्चात उद्यान मंत्री ने पवेलियन में प्रतिभाग कर रहे छह प्रमुख निर्यातकों के स्टॉलों का भ्रमण किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 20 विशिष्ट भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों पर आधारित विशेष गैलरी का भी गहन अवलोकन किया। मंत्री ने प्रदेश की विशिष्ट पहचान वाले इन उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक बाजार में उत्तर प्रदेश के उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सशक्त ब्रांडिंग से प्रदेश के कृषि निर्यात को नई गति मिलेगी।उल्लेखनीय है कि प्छक्न्ै थ्व्व्क्.2026 में विश्व के 32 देशों के पवेलियन स्थापित किए गए हैं। इस मेगा इवेंट में 110 देशों से आए अंतरराष्ट्रीय आयातक और खरीदार भाग ले रहे हैं। भारत के भी लगभग 11 राज्यों ने अपने–अपने पवेलियन के माध्यम से अपनी निर्यात क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इन सभी के बीच उत्तर प्रदेश पवेलियन आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां प्रदेश की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की व्यापक संभावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है।इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि तथा प्रमुख निर्यातक भी उपस्थित रहे।उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के निर्यातकों और उत्पादकों को सीधे वैश्विक खरीदारों से जोड़ना है। इससे न केवल कृषि निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों के प्रदर्शन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

अप्रेंटिसशिप से युवाओं को नई दिशाः वर्ष 2025-26 में 83 हजार से अधिक युवाओं को मिला रोजगारपरक प्रशिक्षण

लखनऊ।उत्तर प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास और रोजगारपरक प्रशिक्षण को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अप्रेंटिसशिप के क्षेत्र में सशक्त पहल की है। प्रदेश में संचालित विभिन्न अप्रेंटिसशिप योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों से जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।वर्ष 2025–26 में अप्रेंटिसशिप योजना के तहत कुल 83,277 युवाओं को उद्योगों एवं एमएसएमई इकाइयों में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए योजित किया गया है। इससे युवाओं को उत्पादन इकाइयों, सेवा क्षेत्र तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से कार्य सीखने का अवसर मिला है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक युवा "सीखते हुए कमाएं" की अवधारणा के तहत उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें।

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को कुशल मानव संसाधन का प्रमुख केंद्र बनाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप योजना के माध्यम से युवाओं को केवल प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि कार्य का वास्तविक और व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं को उद्योगों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

राज्य मंत्री ने बताया कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जा रही प्रतिपूर्ति से अधिष्ठानों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे रोजगारपरक अवसरों का विस्तार हुआ है। राज्य सरकार हर युवा को उसकी क्षमता के अनुरूप कौशल और अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं के तहत संबंधित अधिष्ठानों और अभ्यर्थियों को प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे जहां शिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान आर्थिक सहयोग मिलता है, वहीं अधिष्ठानों को भी प्रशिक्षुओं को रखने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। योगी सरकार का मानना है कि यह मॉडल युवाओं और उद्योगकृदोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है।

अप्रेंटिसशिप के दायरे को व्यापक बनाने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में 795 नए अधिष्ठानों का पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है। इससे विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण के अवसर बढ़े हैं और स्थानीय स्तर पर युवाओं की उद्योगों तक पहुंच आसान हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (सीएमएपीएस) के अंतर्गत 6,164 नए अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।

विभाग के अनुसार, इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को न केवल प्रशिक्षण, बल्कि रोजगारपरक कौशल और औद्योगिक अनुभव भी मिल रहा है, जिससे उनकी नियुक्ति की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

कौशल विकास की इस सतत प्रक्रिया का प्रभाव यह रहा है कि बीते लगभग नौ वर्षों में 4 लाख से अधिक प्रशिक्षु युवाओं को विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में सेवायोजित किया जा चुका है। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को कुशल मानव संसाधन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

योगी सरकार का लक्ष्य है कि अप्रेंटिसशिप को और अधिक व्यापक स्तर पर बढ़ाते हुए युवाओं को उद्योगों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर से जोड़ा जाए। इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल को सुदृढ़ किया गया है और उद्योगों के साथ समन्वय को भी मजबूत किया गया है। सरकार का मानना है कि कुशल युवा न केवल स्वयं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश माहौल को भी सशक्त बनाएंगे।

नेपाल में चुनाव कराने को लेकर भारत-नेपाल के अफसरों की बैठक

लखीमपुर खीरी 08 जनवरी। नेपाल में आगामी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2026 के चुनाव को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को भारत–नेपाल समन्वय समिति की बैठक नेपाल में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। बैठक में दोनों देशों ने चुनाव के दौरान सूचना आदान–प्रदान और सहयोग को सुनिश्चित करने पर सहमति जताई।इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत की ओर से लखीमपुर खीरी और नेपाल की ओर से कैलाली एवं कंचनपुर अंचल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने भरोसा जताया कि चुनाव के दौरान पूर्ण सहयोग और साझा सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।

बैठक की शुरुआत में दोनों देशों के अधिकारियों ने अपना परिचय दिया। बैठक में चुनाव के मद्देनजर सीमा पर चौकसी बरतने, अपराधियों पर लगाम लगाने सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने चुनाव के मद्देनजर सीमा पर विशेष निगरानी रखने की बात कही। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी, अपराधियों की धरपकड़ सीमा के दोनों तरफ कैसे की जाए जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर अपराधियों को संरक्षण ना मिल सके आदि महत्पूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर कार्ययोजना बनाई।इस चुनावी पर्व पर सहयोग की अपेक्षा करते हुए सीडीओ कैलाली हीरालाल रेग्मी और सीडीओ कंचनपुर मदन कोइराला ने कहा कि जितना सहयोग मिलेगा उतना चुनाव कराने में आसानी होगी। हमारे संबंध अच्छे थे और भविष्य में भी बेहतर रहेंगे। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक बंधनों से जुड़े हैं।डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने नेपाल के अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों से जुड़ा है। उन्होंने इसे "रोटी–बेटी का रिश्ता" बताते हुए दोनों देशों के अटूट बंधन पर जोर दिया।बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान शांति, सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करना है।

उन्होंने भरोसा जताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और एसएसबी नेपाल के अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। डीएम ने कहा कि इस संवाद से सीमा सुरक्षा और अपराध नियंत्रण और मजबूत होंगे और सीमावर्ती जनता को सुरक्षित और सहयोगपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि, सूचना का रियल टाइम आदान–प्रदान, और आपात सेवाओं की निर्बाध आवाजाही प्राथमिकताएं रहेंगी। एएसपी पवन गौतम ने कहा कि भारत की ओर से पेट्रोलिंग सतत जारी है। हम नेपाल की ओर से मिलने वाली सूचनाओं पर क्विक रेस्पॉन्ड करेंगे।ये भारतीय अधिकारी रहे मौजूद रू

डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एएसपी पवन गौतम, एसडीएम डॉ अवनीश, राजीव निगम, कमांडेंट 39 बटालियन आरके राजेश्वरी, डिप्टी कमांडेंट ऑपरेशन विजेंद्र कुमार सिंह, कमांडेंट 49 बटालियन शेर सिंह चौधरी, सेकेंड इन कमांडेंट थर्ड बटालियन एम डी तमांग, कमांडेंट 70 बटालियन राजन श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह मौजूद रहे।

पति की मौत के बाद प्रमाण पत्रों के लिए संघर्ष करती पुलिसकर्मी की पत्नी

लखीमपुर–खीरी।सरकार की अनुकंपा नियुक्ति और पारिवारिक पेंशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं कागजों में भले ही आसान दिखाई देती हों, लेकिन जमीनी स्तर पर पीड़ितों को उनका लाभ पाने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम छाउछ का मामला इसका उदाहरण है, जहां एक विधवा महिला को अपने पति की मौत के बाद भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।ग्राम छाउछ के मोहल्ला धीरज नगर कॉलोनी निवासी लक्ष्मी देवी के पति स्वर्गीय अनिल कुमार शर्मा पुलिस विभाग में एसपी कार्यालय, सीतापुर में कार्यरत थे। 13 अगस्त 2025 को उनका आकस्मिक निधन हो गया। परिवार के मुखिया के अचानक चले जाने से आर्थिक स्थिति पूरी तरह डगमगा गई। शासन के नियमों के अनुसार पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, पारिवारिक पेंशन व अन्य विभागीय लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जरूरी प्रमाण पत्र न बनने से सारी प्रक्रिया अटक गई है। पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने निवास और आय प्रमाण पत्र के लिए अब तक तीन बार आवेदन किया, लेकिन हर बार संबंधित लेखपाल अजीत कुमार द्वारा आवेदन को बिना स्पष्ट कारण बताए खारिज कर दिया गया। जब कारण पूछने का प्रयास किया गया तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। लक्ष्मी देवी ने बताया कि उनके नाम से 25 अगस्त 2021 को एक बार निवास प्रमाण पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। उस समय तकनीकी कारणों से आधार संशोधन नहीं हो पाया था। वर्तमान में आधार संशोधन और अन्य शासकीय कार्यों के लिए नया निवास और आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है, इसके बावजूद बार–बार आवेदन खारिज होना सवाल खड़े करता है। पीड़िता का कहना है कि उनके पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक अभिलेख पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। इसके बाद भी यदि प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं तो यह सीधे तौर पर लापरवाही और मनमानी को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री पोर्टल पर पहुंचा मामला

लगातार हो रही अनदेखी से परेशान होकर लक्ष्मी देवी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए पूरे मामले की जांच और शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए तो अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।मामले को लेकर जब लेखपाल संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है और तथ्यों की जांच की जा रही है। यदि तथ्य सही है तो दस्तावेज अवश्य बनाए जाएंगे।

एसडीएम सदर अश्विनी कुमार ने कहा कि प्रार्थना पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ कार्यालय भेज दीजिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सरकारी दावों पर सवाल

यह मामला शासन के उन दावों पर सवाल खड़े करता है, जिनमें कहा जाता है कि विधवाओं और आश्रितों को समयबद्ध तरीके से सरकारी लाभ दिए जाएंगे। पति की मौत के बाद नौकरी की आस लगाए बैठी महिला आज भी प्रमाण पत्रों के लिए भटकने को मजबूर है। जब एक पुलिसकर्मी के परिवार को ही समय पर न्याय और सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी।

जल मिशन योजना के तहत लगी टंकी बनी शोपीस

मैगलगंज खीरी। प्रदेश सरकार की हर घर जल योजना के तहत करोड़ रुपयों की लागत से बनी पानी की टंकियां महज शोपीस बनी हुई है। इन टंकियां में पानी की सप्लाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।जल मिशन योजना के तहत मैगलगंज कस्बे में बनी पानी की टंकी में पानी की सप्लाई न शुरू होने के चलते कहीं न कहीं यह योजना शुरू होने से पहले ही कागजों पर दम तोड़ चुकी है।इस बाबत क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब इन टंकियां में पानी सप्लाई ही नहीं होना था तो यह महज शोपीस क्यों लगाई गई।

अपर पुलिस महानिदेशक ने किया पलिया थाने का आकस्मिक निरीक्षण

लखीमपुर खीरी।अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ सुजीत पाण्डेय द्वारा जनपद खीरी के थाना पलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण व विभिन्न रजिस्टर्स का अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये एवं अधिकारी कर्मचारियों के साथ गोष्ठी की गई।अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ, जोन लखनऊ सुजीत पाण्डेय द्वारा पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा के साथ थाना पलिया का निरीक्षण किया गया। थाना पलिया पुलिस सलामी गार्द द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक को सर्वप्रथम सलामी दी गई। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक, कम्प्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा सम्पूर्ण थाना परिसर एवं कार्यालय की नियमित साफ सफाई हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। साथ ही महोदय द्वारा कार्यालय में रखे विभिन्न महत्वपूर्ण अभिलेखों–अपराध रजिस्टर, आर्डर बुक न्यायालय, आर्डर बुक न्यायालय एन बी डब्ल्यू कुर्की, आर्डर बुक न्यायालय सम्मन, गुण्डा रजिस्टर, समाधान दिवस रजिस्टर, सम्पूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर, महिला उत्पीड़न रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर आदि का बारीकी से निरीक्षण करते हुए रजिस्टर्स के व्यवस्थित रख–रखाव तथा उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिये गये । महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही कर उनका विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। थाने पर लंबित विवेचनाओं का गुण दोष के आधार पर समयबद्ध विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। इसी के साथ थाने पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क एवं मिशन शक्ति केन्द्र की समीक्षा करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण हेतु दिशा–निर्देश दिए गए । साथ ही किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाने हेतु निर्देशित किया गया ।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, ४० वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी २/३७६ रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ० प्र० से प्रकाशित।

सम्पादक

आरती पाण्डेय

ek-

9807059191- 9026560178

Email-

adbhutsamachar@gmail.com

adbhutsamachar@hotmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।